हालिया जन संघर्ष और गैर सरकारी संगठन

दिसम्बर **2010** में ट्यूनीशिया से शुरू हुआ जन उभार महज **7–8** माह में समूचे अरब को अपनी ज़द में लेने के साथ यूरोप अमेरिका तक जा पहुंचा। अभी भी यह जन उभार किसी न किसी रूप में जारी है। इन संघर्षों में मजदूर मेहनतकश जनता–छात्रों–नौजवानों की व्यापक भागीदारी ने जहां पूरी दुनिया के मेहनतकश आवाम में उत्साह का संचार किया वहीं इन संघर्षों में साम्राज्यवाद द्वारा पोषित गैर सरकारी संगठनों के व्यापक प्रभाव ने परिवर्तनकामी ताकतों के सामने बड़ी चुनौती भी पेश की है।

गैर सरकारी संगठनों का विशालकाय तानाबाना आज समूची दुनिया में फैला हुआ है। यह ट्यूनीशिया–मिश्र के संघर्ष में कार्यरत है तो लीबिया–सीरिया में भी। यह यूरोप के इंडिग्नोस तथा कटौती कार्यक्रम (आस्टेरिटी) के खिलाफ संघर्षों में कार्यरत है तो अमेरिका के 'आक्यूपाई वाल स्ट्रीट' आंदोलन में भी मौजूद है।

खुद भारत में भी लाखों की संख्या में गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) मौजूद हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन तो इन्हीं संस्थाओं द्वारा रचा बुना फैलाया आंदोलन था। दलित आंदोलन, नारी आंदोलन, पर्यावरण के सवाल से लेकर आदिवासी संघर्ष, परमाणु ऊर्जा–बड़े बांध के विरोध तक ये गैर सरकारी संगठन हर कहीं फैले हैं। ये रिसर्च संस्थानों से लेकर छात्रों–नौजवानों के संघर्षों, ग्रामीण विकास से लेकर प्रौढ़ शिक्षा हर काम में लिप्त हैं। यानी देश व हर गांव–कस्बे तक ये फैले हैं समाज के हर संघर्ष, हर हलचल में इनकी कम या ज्यादा भूमिका है।

गैर सरकारी संगठनों का यह व्यापक मकड़जाल भारत और दुनिया भर के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करता है। इस लेख में हम इन गैर सरकारी संगठनों की उत्पत्ति–विकास के साथ हालिया जनसंघर्षों में इनकी पूंजीवाद–साम्राज्यवाद परस्त भूमिका की चर्चा करेंगे।

1. गैर सरकारी संगठन : उत्पत्ति व विकास

आज के गैर सरकारी संगठनों के प्रारम्भिक बीज अतीत की ईसाई मिशनरी गतिविधियों में देखे जा सकते हैं। यूरोपीय मिशनरियां अपने प्रारम्भिक काल में अफ्रीकी–एशियाई उपनिवेशों में धर्मांतरण व अन्य गतिविधियों के साथ साम्राज्यवादी सत्ता का समर्थन व सहयोग करती रही हैं। अमेरिकी मिशनरियां उन्नीसवीं सदी के दूसरे दशक से ही पहले लातिन अमेरिका व बाद में पूरी दुनिया में ही अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए राजनीतिक अस्त्र के बतौर काम करने लगी थीं। चर्च व साम्राज्यवादी सत्ताओं से नजदीकी तौर पर जुड़ीं, इनके धन से संचालित ये मिशनरियां साम्राज्यवादी प्रभुत्व के प्रसार का माध्यम बनीं।

उन्नीसवीं सदी का अंत आते–आते दुनिया में समाजवाद के लिए संघर्ष जोर पकड़ने लगा था। साम्राज्यवाद का अपने चिर शत्रु समाजवाद के लिए संघर्ष से सामना होना शुरू हो गया। ऐसे में समाजवाद–साम्यवाद पर वैचारिक हमले के लिए इन्हीं मिशनरियों व चर्च द्वारा गठित अन्य स्वयंसेवी संगठनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इन मिशनरियों–स्वयंसेवी संगठनों ने बाद में अमेरिका के जासूसी कार्यक्रमों के लिए आवरण का भी काम किया। 1948 में पूरी दुनिया में फैली केवल प्रोटेस्टैण्ट मिशनरियों की संख्या 2,530,000 थी।

चर्च व साम्राज्यवादी सत्ताओं के सहयोग–आर्थिक मदद से चलने वाली मिशनरियों के अगले चरण में साम्राज्यवादी धनाढ्यों द्वारा सीधे अपने हित में अपने धन से स्थापित की गयी फाउण्डेशनें अस्तित्व में आयीं। अमेरिका में 1911 में स्टील सम्राट कार्नेगी ने कार्नेगी फाउण्डेशन व 1914 में तेल सम्राट राकफेलर ने राकफेलर फाउण्डेशन की स्थापना की। बाद के दौर में 1936 में मोटर वाहन सम्राट फोर्ड ने फोर्ड फाउण्डेशन की स्थापना की। अन्य साम्राज्यवादी देशों में भी ऐसे ढेरों फाउण्डेशन अस्तित्व में आने लगे। इन फाउण्डेशनों की स्थापना के साथ ही इन लुटेरी कम्पनियों ने संत का चोंगा पहन लिया। खुद अपने ही द्वारा पैदा की गयी भूख और गरीबी को दूर कराने के छद्म प्रयासों द्वारा अपनी काली करतूतों पर इन्होंने पर्दा डालना शुरू किया। जनसामान्य पर जारी औपनिवेशिक लूट से इन्होंने ध्यान भटकाने का प्रयास किया। उपनिवेशों में फैल रही जन संघर्षों की आंधी को कमजोर करने की रणनीति तैयार की। खुद साम्राज्यवादी मुल्कों में पनप रहे जनाक्रोश पर पानी डालने का इन्होंने काम किया और इस सबके लिए उन्होंने अरबों डालर खर्च किये।

1930 की महामंदी के समय इन फाउण्डेशनों ने स्वास्थ्य–शिक्षा–जनकल्याण के कामों का आंशिक बोझ अपने सिर पर ले जनता के आक्रोश से राज्य की रक्षा की। 1924 में राकफेलर और कार्नेगी फाउण्डेशनों ने मिलकर कांउसिल फॉर फारेन रिलेशंस (CFR) की स्थापना की। यह आज भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली विदेशी नीति दबाव समूह है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में भी इसका सहयोग रहा। अमेरिकी राज्य के गृहसचिव व विश्व बैंक के अध्यक्ष सी.एफ.आर. से सीधे संबंधित रहते रहे हैं।

राकफेलर फाउण्डेशन के दो प्रमुख लक्ष्य रहे हैं पहला चिकित्सा अनुसंधान के लिए संसाधन जुटाना दूसरा समूची दुनिया में ईसाई मूल्यों और पश्चिमी सभ्यता की स्थापना करना। फोर्ड फाउण्डेशन के लक्ष्यों में स्वतंत्रता व लोकतंत्र के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करने के साथ शैक्षिक क्षेत्र में काम करना था। लोकतंत्र के विकास के नाम पर इसके अनुदानों के जरिये नये आजाद मुल्कों को समाजवाद की ओर बढ़ने से रोकने में भूमिका निभायी गयी। शीत युद्ध के समय इसके द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाओं ने पश्चिमी साम्राज्यवादियों के हित में शोध से लेकर अन्य कामों को संचालित किया। फोर्ड फाउण्डेशन के बारे में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा था :

> ''सब कुछ जो फाउण्डेशन ने किया उसे दुनिया को पूंजीवाद के लिए सुरक्षित बनाना माना जा सकता है। ऐसा उसने पीड़ितों को मदद पहुंचाकर सामाजिक तनाव कम करके, आक्रोशितों के लिए सेफटी वाल्व का काम करके, और सरकार की कार्यशैली बेहतर बनाकर किया। (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.सी.जार्ज बन्डी के राष्ट्रपति केनेडी व फोर्ड फाउण्डेशन अध्यक्ष लिंडन जानसन से वार्ता में व्यक्त विचार)

दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव आ चुके थे। ताकतवर फ्रांसीसी–ब्रिटिश–जर्मन साम्राज्यवादी राष्ट्र युद्ध में ध्वस्त हो चुके थे और अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक–सामरिक ताकत के रूप में उभर चुका था। पूंजीवादी दुनिया के सम्मुख समाजवादी खेमा अब एक देश से कई देशों में फैल नयी चुनौती पेश कर रहा था। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की धारा के आगे बढ़ने से ढेरों देश साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त हो रहे थे।

ऐसे में साम्राज्यवादी ताकतों के सामने जो लक्ष्य थे उनमें सर्वप्रमुख समाजवादी खेमे से निपटना था। इसके साथ ही नव–स्वाधीन देशों को अपने आर्थिक चंगुल में जकड़ उन्हें समाजवाद की दिशा में बढ़ने से रोकना था। और फिर अपनी पूंजी व तकनीक के निर्यात के जरिये साम्राज्यवादी लूट व शोषण जारी रखना तो था ही।

इस दौर में गैर सरकारी संगठनों के कार्यों का स्वरूप भी बदलने लगा। अब इन्होंने समुदाय के सामूहिक हितों के मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया। अब फाउण्डेशनों ने मध्य व उच्च वर्ग के स्वयं सेवकों को महिला क्लबों, अस्पतालों, रोटरी क्लबों में सक्रिय करना शुरू कर दिया। ट्रू मैन के चार सूत्री कार्यक्रम ने 40 के दशक में अमेरिका के नव–उपनिवेश बनाने की नीति में मदद पहुंचाई।

1947 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. की स्थापना हुई। सी.आई.ए. से सहयोग करते हुए अमेरिकी फाउण्डेशनों ने तमाम ऐसे संगठन खड़े किये जो समाजवाद को न सिर्फ नकारते थे बल्कि उसके खिलाफ प्रचार व संघर्ष करने को तत्पर थे।

साम्राज्यवाद द्वारा मौजूद उपनिवेशों–नवउपनिवेशों व नव–स्वाधीन देशों के लिए औपचारिक सहायता कार्यक्रम चलाया गया। इसके साथ था 'अतिरिक्त सामग्री कार्यक्रम' जो अमेरिका द्वारा 1954 के PL 480 एक्ट के जरिये 'शान्ति के लिए खाद्यान्न कार्यक्रम' में बदल गया। इस अमेरिकी कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता के जरिये गरीब मुल्कों पर शिकंजा कसना था। गैर सरकारी संगठन इस सहायता कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ सहयोग में कार्य करते हुए साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करने में लग गये। 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन' नामक अमेरिकी औपचारिक संगठन अमेरिकी एग्री बिजनेस निगमों की अतिरिक्त कृषि उपज को पूरी तीसरी दुनिया के देशों में पहुंचाने का काम करने लगा। इस सहायता के बदले अमेरिकी शासक तीसरी दुनिया के शासकों पर अपने पक्ष में नीति बनाने का दबाव डालते थे। कालान्तर में यही 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन' यू.एस.एड. -USAID (US Agency For international Development) का जन्म दाता बना।

1950 के दशक में स्वेज संकट, क्यूबा में क्रांति जैसी कई घटनाओं ने अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती प्रदान करनी शुरू की। ऐसे में केनेडी ने 'प्रगति समझौता' कार्यक्रम संचालित कर समाजवाद के विरुद्ध लड़ाई तेज कर दी और साथ ही गरीब देशों में 'दान पुण्य' (चैरिटी) भी बढ़ा दिया। इस सब कामों के लिए यू.एस.एड. (USAID) पैसा बहाने लगा। 1961 में अमेरिकी सरकार ने 'शान्ति कोर' (Peace Corps) स्थापित किया जिसका लक्ष्य शान्ति दूतों के जरिये अमेरिकी साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्रसारित करना था। 1966 तक 52 देशों में 15,556 शान्तिदूत सक्रिय थे।

इसी काल में यू.एस.एड., शान्ति कोर, सी.आई.ए. व एकाधिकारी पूंजीपतियों के गठबन्धन ने दूसरे देशों की जानकारी जुटाने के लिए व्यापक अनुसंधान की शुरुआत की। अमेरिका में मिडवेस्ट यूनिवर्सिटी कन्सोर्टियम फॉर इन्टरनेशनल एक्टिविटीज (Midwest Univercity Consortium For International Activities -MUCIA) की स्थापना के साथ ढेरों अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के विशिष्ट केन्द्र गठित किये गये। इनके विद्यार्थी गैर सरकारी संगठनों के भावी कर्णधार बनने के साथ समाजवाद से लड़ना भी सीखते थे। सी.आई.ए. ने इसके अलावा अमेरिकी नियंत्रण में वृद्धि के लिए अन्य अनुसंधानों को भी शुरू करवाया जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क पर तकनीक के उपयोग से नियंत्रण कायम करना था। गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य के इन अनुसंधानों का माध्यम बने।

अमेरिका के अलावा यूरोपीय साम्राज्यवादी भी 60 के दशक से गैर सरकारी संगठनों पर पर्याप्त ध्यान देने लगे। सभी प्रमुख देशों में बाकायदा अन्य देशों के विकास व सहयोग के नाम पर इन गैर सरकारी संगठनों पर नियंत्रण के लिए मंत्रालय या सरकारी संगठन कायम कर दिये गये।

70 का दशक आते–आते पूंजीवादी विकास का स्वर्ण युग बीत चुका था और पूंजीवादी–साम्राज्यवादी तंत्र आर्थिक ठहराव का शिकार हो चुका था। कल्याणकारी राज्य का कीन्स का मॉडल भी पूंजीवाद को संकट में जाने से नहीं बचा पाया। ऐसे में कल्याणकारी राज्य का चोंगा उतार जिन नई नीतियों को पूरी दुनिया में फैलाया जाना था उनमें सरकारी राहत, कल्याण–स्वास्थ्य–शिक्षा के मदों में कटौती, मजदूर वर्ग की मजदूरी में गिरावट, खुली प्रतियोगिता आदि का बोलबाला था। उदारीकरण– निजीकरण–वैश्वीकरण के इस दौर में पूंजी ने श्रम पर खुला हमला बोल दिया। ऐसे में अब सरकार कल्याण के कार्यक्रमों से हाथ पीछे खींच रही थी तब गैर सरकारी संगठनों ने इन कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना शुरू किया। इस दौर में इनका फैलाव अभूतपूर्व ढंग से बढ़ गया। इसी दौर में नव–वाम और उत्तर आधुनिक विचारधारा जोर–शोर से प्रचारित की गई। इन सबका उद्देश्य वर्ग आधारित सोच से ध्यान भटकाना था।

अब तमाम गैर सरकारी संगठन (NGO) संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ घनिष्ठ सहयोग में खड़े हो गये। भांति–भांति के क्षेत्रों गरीबी, बेरोजगारी, दलित, अश्वेत, आदिवासी, नारी, पर्यावरण आदि में अलग–अलग अनुसंधान करने व इन्हें अलग–अलग सम्बोधित करने वाले संगठन पैदा हो गये। 'जन केन्द्रित विकास' के उद्देश्य के तहत गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाने लगे। ग्रामीण विकास, फल प्रबन्धन से लेकर भांति–भांति के काम इनके दायरे में आ गये।

विश्व बैंक के सहयोग के चलते 1980 के दशक में विश्व बैंक–गैर सरकारी संगठनों (WB-NGO) की एक कमेटी की स्थापना हुई इसके तहत जनता का गुस्सा शान्त करने के लिए पानी डालने का काम भी शुरू हो गया। साम्राज्यवाद पोषित स्वयं सेवी संस्थाओं ने 'साम्राज्यवाद विरोध' से लेकर 'उदारवादी नीतियों का विरोध,' 'भ्रष्टाचार' से लेकर 'गैट विरोध' तक का काम शुरू कर दिया।

टिकाऊ विकास (Sustainable Development) का नारा बुलन्द करते हुए इन गैर सरकारी संगठनों ने इसे अपना घोषित दर्शन बना लिया। जनसंख्या नियंत्रण से विकास के लिए जन पहलकदमी की बातें करते हुए ये बहुराष्ट्रीय निगमों की करतूतों पर चुप्पी साध जाते थे।

1980 का दशक आते आते शुरू हुआ रीगन का 'प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी'। दरअसल यह ट्रू मैन व केनेडी के कार्यक्रमों से आगे का कदम था। इससे गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों को नया क्षेत्र मिला। अब इसके तहत गठित संगठनों का उद्देश्य 'लोकतंत्र' का प्रसार था। ये गैर सरकारी संगठन सी.आई.ए. द्वारा गुप्त रूप से किये जाने वाले कार्यों को खुले रूप में करने लगे। इसके तहत अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा जनवाद के प्रसार के बहाने अपने विरोधी संघर्षों को कुचलने के साथ अपनी पिट्ठू सरकारों पर नियंत्रण और विरोधी सत्ताओं को पलटने के दुष्कर्म किये जाने लगे।

प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी साम्यवाद विरोधी मिशन था। इसका एक अन्य उद्देश्य पुरानी ट्रेड यूनियनों की जगह एन.जी.ओ. मार्का ट्रेड यूनियनों का गठन था इसके लिए सी.आई.ए. व हावर्ड फाउण्डेशन द्वारा ट्रेनिग कार्यक्रम भी चलाया गया। मजदूर हड़तालों आदि में सहयोग के नाम पर सक्रिय ये एन.जी.ओ. उन्हें तोड़ने का काम करने लगे। इसी तरह के संगठन जर्मनी में 'फेडरल इंटलिजेंस सर्विस' से मिलकर काम करते हैं। ये विश्व स्तर पर तथाकथित आत्मनिर्भर ट्रेड यूनियनों का तानाबाना खड़ा करने का काम करते हैं। साथ ही ढांचागत समायोजन से विस्थापित मजदूरों के समायोजन की भी इनकी नीति है।

कुल मिलाकर 70 के दशक के बाद एन.जी.ओ. नेटवर्क ने उन सभी जगहों पर अपनी भूमिका बना ली जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों के कार्यक्षेत्र थे। किसान, आदिवासी, मजदूर कोई भी इनकी जद से बाहर नहीं है।

90 के दशक में नव–उदारवादी नीतियों के परिणाम मेहनतकश जनता की बदहाली के रूप में सामने आने लगा। ऐसे में 'वैश्वीकरण विरोध' का क्षेत्र भी गैर सरकारी संगठनों के लिए विस्तृत होता चला गया। इसी के साथ पर्यावरण का मुद्दा भी ढेरों गैर सरकारी संगठनों का पंसदीदा विषय बन गया।

जिन कारपोरेट घरानों के हित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन द्वारा आगे बढ़ाये जा रहे थे उन्हीं से जुड़ी फाउण्डेशनें इन संस्थाओं के विरोध के नाम पर पैसा बहाने लगी। कुछ गैर सरकारी संगठन इन वैश्विक संगठनों (आई.एम.एफ.,डब्लू.बी.,डब्लू.

टी.ओ.) के साथ जुड़ वैश्वीकरण को मानवीय चेहरा देने में जुट गये तो कुछ ने इनके छद्म विरोध का झण्डा उठा लिया। कुछ ने दोनों तरह के कामों का जिम्मा ले लिया।

वैश्वीकरण को 'मानवीय' चेहरा दिलाने में लगी संस्थाओं में सॉप्रीन (Structural Adjustment Participatory Review Initiative), जो कि वैश्विक सिविल सोसाइटी नेटवर्क है तथा द ट्रेड आब्जर्वेटरी (मीनियोलिस स्थित कृषि व व्यापार नीति के संस्थान का एक प्रोजक्ट) प्रमुख हैं। जहां साप्रीन विश्व बैंक, डेवलपमेंट गैप, यू.एस.एड व विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों द्वारा खड़ा किया गया वहीं ट्रेड आब्जर्वेटरी फोर्ड, राकफेलर, मैक्नाइट, जौयसी, जान. डी. कैथरीन, टीमैक आर्थर, बाउमैन फैमिली, जेनिफर, अल्टमैन आदि फाउन्डेशनों द्वारा वित्तपोषित हैं।

वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम की बैठकों में ऑक्सफेम, एमनस्टी इंटरनेशनल, ग्रीनपीस सरीखे संगठन बुलाये जाने लगे।

इसी तरह ब्राजील के कुछ एन.जी.ओ. और फ्रांस के अटाक द्वारा 2001 में विश्व सामाजिक मंच स्थापित किया गया। अटाक फ्रांसीसी एन.जी.ओ. प्लेटफार्म है इस प्रक्रिया में ब्राजील की वर्कर्स पार्टी का पूर्ण सहयोग रहा। डब्लू.एस.एफ को मुख्यतः वित्तपोषित करने वाली फाउण्डेशनें जर्मन ग्रीन पार्टी द्वारा नियंत्रित हेनरिच बोएल फाउण्डेशन, ऑक्सफाम (यू.के.), नोविब (हालैण्ड) व एक्शन एड (यू.के.) आदि हैं। फोर्ड फाउण्डेशन इसे अप्रत्यक्ष तरीके से अनुदान देता रहा है।

डब्लू.एस.एफ. की अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल में जहां एन.जी.ओ., ट्रेड यूनियन, मीडिया संगठन, रिसर्च संस्थान शामिल है जिनमें अधिकतर बड़ी फाउण्डेशनों के सहयोग से चलते हैं। वहीं फंड दाताओं का नेटवर्क एफ.टी.एन.जी. (The Funders Network on Trade and Globalization) इसका पर्यवेक्षक है। एफ.टी.एन.जी. में फोर्ड फाउण्डेशन, राकफेलर ब्रदर्स, हेनरिच बोएल, सी.एस. मौट, मेर्क फैमिली फाउण्डेशन, ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट, टाइड आदि शामिल हैं।

डब्लू.एस.एफ का उद्देश्य 'वैश्वीकरण विरोध' के नाम पर वैश्विक संस्थाओं (डब्लू.बी., आई.एम.एफ., डब्लू.टी.ओ.) में मामूली फेरबदल के साथ नीचे से वैश्वीकरण की शुरुआत करना था। इसका बोलबाला पिछले दशक की तुलना में अब कम हो गया है।

इसी तरह यूरोपीय यूनियन के देशों की सरकारें व फाउन्डेशनें–यूरोपीय यूनियन की बैठकों का विरोध करने वाले गैर सरकारी संगठनों को पालती रही हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाली जनता व सामान्य कार्यकर्ताओं का पुलिस द्वारा दमन भी किया जाता रहा है।

गैर सरकारी संगठनों की दोहरी भूमिका रही है। पूंजीवादी व्यवस्था के चलते पैदा होने वाले असंतोष को कुछ राहत प्रदान कर कम करना और असंतोष को व्यवस्था के दायरे में अभिव्यक्त करना। इसके साथ ही जब जनता विद्रोह के लिए उठ खड़ी हो जाय तो विद्रोही जनता का ध्यान बंटाने के लिए लीवर का काम करना या यूं कहें कि विद्रोह को भी व्यवस्था के दायरे में ही समेट देना।

डब्लू.एस.एफ. से लेकर तमाम तामझाम इस लीवर की भूमिका के लिए ही खड़ा किया गया है। वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम तक में एन. जी.ओ. कारकूनों की भागीदारी करा वैश्वीकरण लागू कराने और डब्लू.एस.एफ. के जरिये उसके 'विरोध' दोनों को साम्राज्यवादी नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं।

इन गैर सरकारी संगठनों के मुख्य कर्ताधर्ता जहां अक्सर उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं वहीं इनके आम कार्यकर्ता मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग के नौजवानों–छात्रों–पेशेवरों–नागरिकों से लेकर निम्न वर्ग के मजदूर–किसान तक हो सकते हैं। व्यवस्था से आक्रोशित या असंतुष्ट लोगों का बड़ा समूह जो सही राजनीति पर खड़े होकर क्रांतिकारी राजनीति का झण्डाबरदार बन सकता था इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा 'समाजसेवा के साथ कमाई भी' के प्रलोभन से अपने भीतर समेट लिया जाता है। इसी तरह ये संगठन क्रांतिकारी ताकतों को भी भ्रष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं।

2.साम्राज्यवाद, जनवाद और गैर सरकारी संस्थायें

साम्राज्यवाद अपने आप में जनवाद विरोधी, जनवाद को सीमित करने वाली प्रतिक्रियावादी व्यवस्था है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. का पूरा इतिहास ही दूसरे देशों में षड्यंत्र–तख्तापलट का इतिहास है। लातिन अमेरिका से लेकर अरब दुनिया तक उसने सैकड़ों बार लोकप्रिय, अपनी विरोधी सरकारों का तख्ता पलट कर साम्राज्यवाद परस्त सत्ताएं कायम की हैं। सीधे सैन्य हमले से लेकर विद्रोही गुटों की मदद आदि हरेक सम्भव हथकंडों के जरिये साम्राज्यवाद ने स्वतंत्र गरीब मुल्कों की आजादी छीनने की कोशिश की है। पूरा इतिहास ही उसके खून सने जन विरोधी कारनामों से भरा पड़ा है।

वैश्विक प्रभुत्व की अपनी आकांक्षा से साम्राज्यवादियों को इतने पर भी चैन नहीं पड़ा तभी उन्होंने 'लोकतंत्र का प्रसार' करने वाली संस्थायें गठित करनी शुरू कर दीं। भेड़िये भेड़ की स्वतंत्रता का नारा देकर अपने हित साधने में जुट गये। साम्यवाद के खिलाफ लोकतंत्र की वकालत का काम तो पहले से चल रहा था पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और खासकर 80 के दशक से इसका बोलबाला बहुत बढ़ गया। इस उद्देश्य से ढेरों संस्थाएं गठित की जाने लगीं। उनके जरिये ढेरों देशों के राजनैतिक समूहों को भारी अनुदान के साथ प्रभावित किया जाने लगा। इस दिशा में अनुसंधान व व्यवहारिक कार्यवाहियों हेतु सैकड़ों गैर सरकारी संगठन उगने लगे।

1982 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इंग्लैण्ड में वेस्टमिंस्टर पैलेस में 'लोकतंत्र और शांति प्रोत्साहन' शीर्षक के अपने संबोधन में प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी की अवधारणा प्रस्तुत की :

> ''हमारा आज ठीक–ठीक मिशन है–स्वतंत्रता और साथ ही शांति को संरक्षित करना। देखने में यह सरल नहीं लगता लेकिन मेरा विश्वास है कि हम एक मोड़ बिन्दु पर हैं। विचित्र विडम्बनापूर्ण अर्थ में (in an ironic sense) कार्ल मार्क्स सही थे। आज हम एक महान क्रांतिकारी संकट देख रहे हैं। एक संकट जहां आर्थिक व्यवस्था की मांगें राजनैतिक व्यवस्था से सीधे टकरा रही हैं। लेकिन संकट स्वतंत्र, गैर मार्क्सवादी पश्चिम में नहीं बल्कि खुद मार्क्सवाद–लेनिनवाद के घर सोवियत संघ में घटित हो रहा है। यह सोवियत संघ है जो अपने नागरिकों की मानव स्वतंत्रता और मानव गरिमा को नकार इतिहास के ज्वार के खिलाफ चल रहा है। ... ...
>
> ''सोवियत प्रयोग का क्षय हमें आश्चर्य चकित नहीं करेगा। जहां भी स्वतंत्र और बन्द समाजों की तुलना की जाय चाहे वो पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया, मलेशिया और वियतनाम हो, ये लोकतांत्रिक देश ही हैं जो सम्पन्न हैं और अपनी जनता की जरूरतों की पूर्ति कर रहे है। ... ...
>
> ''कोई लोकतंत्र नाजुक फूल नहीं होता फिर भी इसे पालने पोसने की जरूरत होती है। अगर इस सदी के शेष समय को स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक आदर्शों में निरन्तर वृद्धि देखनी है तो हमें लोकतंत्र के अभियान के लिए कार्यवाही करनी होगी।
>
> ''हम यह तथ्य अनदेखा नहीं कर सकते कि हमारे प्रोत्साहन के बगैर भी तानाशाहियों के खिलाफ निरन्तर विस्फोट होते रहे हैं और होते रहेंगे। सोवियत संघ भी इस हकीकत से परे नहीं है। ... ...

''हमें बदलाव की गति को तेज करते हुए सावधान रहना होगा पर हमें अपने अन्तिम उद्देश्यों को घोषित करने और उनकी ओर बढ़ने के लिए ठोस कार्यवाही में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

'' हमने अमेरिका में कुछ अन्य कदम उठाने की योजना बनाई है जैसा कि हमारे कई सहयोगी पहले ही इस समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर चुके हैं। नेशनल रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन व अन्य नेता द्विदलीय अमेरिकी राजनैतिक फाउन्डेशन के साथ एक अध्ययन शुरू कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में लोकतंत्र के वैश्विक अभियान में सहयोग कर सकता है। यह अब जोर पकड़ रहा है। वे दोनों पार्टियों के कांग्रेस नेताओं, बिजनेस व श्रम प्रतिनिधियों और हमारे समाज की अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के सहयोग से ऐसा करेंगे।'' (June 8, 1992, अमेरिकी राष्ट्रपति का वेस्टमिंस्टर पैलेस, इंग्लैण्ड में भाषण, स्रोत : NED website www.ned.org)

उपरोक्त सम्बोधन से स्पष्ट है कि अमेरिका का प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी सोवियत साम्राज्यवाद की बदहाली के बहाने मार्क्सवाद–लेनिनवाद पर कीचड़ उछालने, उसकी तुलना में पूंजीवादी लोकतंत्र को श्रेष्ठ व्यवस्था के बतौर प्रस्तुत करने का औजार है। अमेरिकी सैन्य हमलों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ खड़े राष्ट्रों को लोकतंत्र स्थापना के आवरण के तहत भीतर से कमजोर किया जाना था।

1983 में नेशनल इन्डॉवमैंट फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना के तहत अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को व्यवहारिक रूप दे दिया। अमेरिकी कांग्रेस ने इसके कार्य करने के 6 उद्देश्य सृजित किये जिन्हें इसने अपने सिद्धान्तों और उद्देश्यों सम्बन्धी वक्तव्य (Statement of Principals & objectivè) में शामिल किया।

''इंडॉवमेंट के द्वारा समर्थित कार्यवाहियां उन छः उद्देश्यों से संचालित होती हैं जो इंडॉवमेंट के 'आर्टिकिल ऑफ इनकारपोरेशन' और अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित 'नेशनल इंडॉवमेंट फॉर डेमोक्रेसी' एक्ट द्वारा निर्देशित कर दिये गये हैं। ये 6 उद्देश्य हैं,

- निजी क्षेत्र की पहलकदमी के द्वारा पूरी दुनिया में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, इनमें व्यक्तिगत अधिकार व स्वतंत्रता (अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिर्तिं मानवाधिकारों के साथ) को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां, जो कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्य करने के लिए जरूरी हैं, शामिल हैं।
- अमेरिका के निजी क्षेत्र के ग्रुपों (विशेषकर दो प्रमुख अमेरिकी राजनैतिक पार्टियों, श्रम और बिजनेस) और विदेशी लोकतांत्रिक ग्रुपों के बीच आदान प्रदान सुनिश्चित करना।
- विदेशों में लोकतंत्र ट्रेनिंग कार्यक्रम व लोकतांत्रिक संस्थायें निर्मित करने में अमेरिका की गैर सरकारी भागीदारी (विशेषकर दो प्रमुख अमेरिकी राजनैतिक पार्टियों, श्रम, बिजनेस व अन्य निजी क्षेत्र के ग्रुपों के जरिये) को प्रोत्साहित करना।
- विदेशों में लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को स्वदेशी लोकतांत्रिक ताकतों के निरंतर सहयोग से मजबूत करना।
- विदेशों में सांस्कृतिक मूल्यों, लोकतांत्रिक बहुलतावाद को समर्पित संगठनों, संस्थाओं के साथ प्रमुख अमेरिकी राजनैतिक पार्टियों, श्रम, बिजनेस व अन्य निजी क्षेत्र के ग्रुपों के सहयोग का समर्थन करना।
- लोकतंत्र की स्थापना और विकास को इस तरीके से प्रोत्साहित करना कि वो अमेरिका के व्यापक राष्ट्रीय हितों के साथ और अन्य देशों के लोकतांत्रिक ग्रुपों, जिनके कार्यक्रमों की इन्डॉवमेंट मदद करता हो के साथ सामंजस्य में हो। (Statement of principals & objectives, NED website)

एन.ई.डी. का उद्देश्य जहां एक ओर अमेरिका के नेतृत्व में उसके प्रभुत्व का प्रसार करना था जिसमें निजी पूंजी को खुली छूट हासिल होनी थी। इसके साथ ही बहुलवाद (Pluralism) के तहत प्रमुख उद्देश्य वर्गीय राजनीति के बरक्स अलग अलग पहचानों–मुद्दों की राजनीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करवाना था। ट्रेड यूनियनों को 'स्वतंत्र' के लेबल के तहत वर्गीय राजनीति से दूर करना था। इसके अलावा अमेरिका के विरोधी राष्ट्रों में लोकतंत्र स्थापना के बहाने घुसपैठ करनी थी। तो अन्य देशों को लोकतंत्र की अमेरिकी प्रैक्टिस न करने के लिए दबाव में लेना था।

एन.ई.डी. के 20 वर्ष पूरे होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का भाषण अमेरिकी नीति का पूरी तरह स्पष्ट कर देता है :

''हमारे लोकतंत्र की जड़ें इंग्लैण्ड और इसकी संसद में ढूंढी जा सकती हैं और साथ ही इस संगठन की जड़ें भी। जून 1982 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने वेस्टमिंस्टर पैलेस में बोलते हुए घोषणा की थी कि इतिहास में मोड़ बिन्दु आ चुका है। उन्होंने तर्क किया था कि सोवियत कम्युनिज्म फेल हो चुका है ठीक इसीलिए क्योंकि उसने अपनी जनता, उसकी रचनात्मकता, उसकी योग्यता और उसके अधिकार का सम्मान नहीं किया। ... ...

''अमेरिका ने यूरोप व एशिया में सैन्य व नैतिक प्रतिबद्धता घोषित की जिसने आजाद राष्ट्रों को हमले से बचाया और वे परिस्थितियां पैदा की जिनमें नये लोकतंत्र प्रस्फुटित हो सकें। हमने सम्पूर्ण राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ शोषित लोगों को प्रेरणा भी प्रदान की। जेल कैम्पों, प्रतिबंधित यूनियन बैठकों में, गुप्त (clandestine) चर्चों में, आदमी और औरतें जानते हैं कि पूरी दुनिया उनकी तरह के दुःस्वप्न में नहीं जी रही है। वे जानते हैं कि कम से कम एक जगह–एक चमकती और आशाजनक भूमि है जहां स्वतंत्रता का मोल और सुरक्षा है। और वे प्रार्थना करते है कि अमेरिका उन्हें न भूले या दुनिया में स्वतंत्रता प्रोत्साहित करने के अपने मिशन को न भूले। ... ...

''और अब हमें इस सबक को अपने समय पर लागू करना होगा। हम एक अन्य मोड़ बिन्दु पर पहुंच चुके हैं। और हमारा संकल्प विश्व लोकतांत्रिक आंदोलन के अगले चरण को आकार देगा।

''हमारी लोकतंत्र की प्रतिबद्धता क्यूबा, बर्मा, उत्तर कोरिया और जिम्बॉब्वे जो कि दमन के दुनिया में कुछ ठिकाने हैं, में परीक्षित की गई है। इन देशों के लोग कैद में भय और चुप्पी के साथ रहते हैं तब भी ये सत्तायें स्वतंत्रता को हमेशा के लिए बांधे नहीं रख सकती हैं और एक दिन जेल कैम्पों व जेल सेलों से और निर्वासन से नये लोकतंत्र के नेता आ पहुंचेंगे। कम्युनिज्म, सैन्यवाद और सनकी–भ्रष्ट लोगों का शासन गुजरे युग के अवशेष बन चुके हैं। और हम इन दमित लोगों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि उनकी स्वतंत्रता का दिन न आ जाये।

''लोकतंत्र की हमारी प्रतिबद्धता चीन में परीक्षित की गयी है। इस देश के पास स्वतंत्रता के कुछ टुकड़े हैं तब भी चीन के लोग अपनी सम्पूर्ण व वास्तविक मुक्ति चाहते हैं। चीन ने खोज लिया है आर्थिक स्वतंत्रता से राष्ट्रीय सम्पदा बढ़ती है। चीन के नेता यह भी ढूंढ लेंगे कि राष्ट्रीय महानता व राष्ट्रीय सम्मान के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक व धार्मिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। वास्तव में आदमी और औरतें जिन्हें अपनी खुद की सम्पत्ति पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया है वे अपनी जिंदगी और अपने देश पर नियंत्रण भी मांगेंगे।

''लोकतंत्र की हमारी प्रतिबद्धता मध्य पूर्व में भी परीक्षित की गयी है जो कि मेरा आज का फोकस है और आने वाले कुछ दशकों में अमेरिकी नीति का भी केन्द्र बिन्दु रहेगा। मध्य पूर्व के कई देशों में–बड़े रणनीतिक महत्व वाले देशों में लोकतंत्र ने अभी तक जड़ें नहीं जमाई हैं। और प्रश्न उठता है कि क्या मध्य पूर्व की जनता स्वतंत्रता की पहुंच से बाहर है। लाखों आदमी, औरतें और बच्चे जो इतिहास या संस्कृति द्वारा कुचले गये हैं क्या वे निरंकुशता के तहत ही जियेंगे? क्या वे अकेले कभी स्वतंत्रता को

नहीं जानेंगे और न ही इस मामले में अपनी इच्छा रखेंगे? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं कि हर व्यक्ति के पास आजाद होने की क्षमता और अधिकार है। ... ...

''औपनिवेशिक युग बीत जाने के बाद मध्य पूर्व ने कई सैन्य तानाशाहियां देखी। कुछ शासकों ने समाजवाद की अंधभक्ति को अपना लिया है। उन्होंने राजनैतिक दलों, मीडिया व विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण कर लिया है। वे सोवियत ब्लॉक और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साथ सम्बद्ध हैं। इराक और सीरिया के तानाशाहों ने राष्ट्रीय सम्मान, प्राचीन गौरव की वापसी का वायदा किया था इसके बजाय उन्होंने उत्पीड़न–दमन–व्यथा और बरबादी का साम्राज्य कायम किया। ... ...

''जैसा कि हम इस क्षेत्र में सुधारों को देख व प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमें ध्यान है कि आधुनिकता का मतलब पाश्चात्यकरण नहीं होता। मध्य पूर्व कि प्रतिनिधि सरकारें अपनी संस्कृति प्रदर्शित करेंगी। वे हमारी तरह न हो सकती हैं और न होंगी। लोकतांत्रिक देश संवैधानिक राजतंत्र, संघात्मक गणतंत्र या संसदीय प्रणाली वाला हो सकता है और कार्यकारी लोकतंत्र को विकसित होने में समय लगता है जैसा कि हमारे साथ हुआ हमने समावेश और न्याय की ओर यात्रा के लिए 200 वर्ष लिए और यह हमें धैर्यवान बनाता है और समझाता है कि अन्य देश इस यात्रा के अलग–अलग चरण में हैं। ... ...

''ये सभी सिद्धान्त अफगानिस्तान व ईराक में लागू किये जा रहे हैं। राष्ट्रपति करजई के नेतृत्व में अफगानिस्तान के लोग आधुनिक व शांतिप्रिय सरकार बना रहे हैं। ... ...

''इराक में 'कोलीशन प्रोविजनल अथॉरिटी' और 'इराकी गवर्निंग काउंसिल' लोकतंत्र स्थापना के प्रयास में लगे हैं। ... .

.

''इराक में लोकतंत्र स्थापना कई हाथों का काम है अमेरिका और सहयोगी ताकतें इराक की शान्ति और आजाद राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए त्याग कर रही हैं। कई देशों के सहायता कार्यकर्ता खतरे का सामना कर इराकी लोगों की मदद कर रहे हैं। 'नेशनल इन्डॉवमेट ऑफ डेमोक्रेसी' स्त्री अधिकारों को प्रोत्साहित करने व इराकी पत्रकारों को प्रशिक्षित करने के साथ राजनैतिक भागीदारी के गुर सिखा रही है। (स्रोत : वही)

2003 के बुश के इस भाषण से पूर्व ही अमेरिका ने समूचे मध्य पूर्व एशिया को अपने प्रभुत्व में बनाये रखने, विरोधी सत्ताओं से निपटने की नीति बना ली थी। जाहिर है एन.ई.डी. का इस्तेमाल बहुतायत रूप से इस क्षेत्र में किया जाने वाला था। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा एन.ई.डी. को फंडिंग 1994 में 33 मिलियन डालर से बढ़कर 2008 में 100 मिलियन डालर पहुंच गयी। इस वृद्धि का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व एशिया में निवेश किया जाना था।

एन.ई.डी. के सहयोग व प्रभाव के साथ अन्य देशों द्वारा भी लोकतंत्र समर्थक फाउंडेशनें खड़ी की जाने लगीं। 1992 में ग्रेट ब्रिटेन में 'वेस्टमिंस्टर फॉउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी' का गठन किया गया। आस्ट्रेलिया में 'सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टिट्यूशंस' का गठन हुआ। 2003 में ताइवान ने 'ताइवान फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी' का गठन किया।

2005 में 'यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड' व 2007 में 'अरब डेमोक्रेसी फाउंडेशन' का गठन हुआ। 2008 में 'यूरोपीयन पार्टनरशिप फॉर डेमोक्रेसी' गठित किया गया।

एन.ई.डी. द्वारा 'वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी' का भी गठन किया गया एन.ई.डी. इसके सैक्रेटैरिएट की तरह कार्यरत है इसकी पहली विश्व असेम्बली 1999 में नई दिल्ली में हुई। इसके बाद से 4 और असेम्बली हो चुकी हैं। इसका काम सिविल सोसाइटी की रक्षा–सहायता व वैश्विक लोकतंत्र सहायता का मूल्यांकन करना है।

एन.ई.डी. के साथ पूर्ण सहयोग से काम करने वाला दूसरा अमेरिकी संगठन 'फ्रीडम हाउस' है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। इसके स्थापना करने वालों में ढेरों प्रभावशाली अमेरिकी पत्रकार, पूंजीपति, मजदूर नेता, बुद्धिजीवी व पूर्व सरकारी अफसर थे। इसकी स्थापना नाजीवाद के खिलाफ की गयी थी पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके हमले का निशाना कम्युनिज्म बन चुका था। अपने इतिहास 'Our history' शीर्षक में यह अपने कामों के बारे में कहता :

''एक सर्वसत्तावादी बुराई नाजीवाद के प्रतिकार में बनाये गये फ्रीडम हाउस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महान बीसवीं सदी की दूसरी सर्वसत्तावादी (Totalitarian) धमकी कम्युनिज्म के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। संगठन के नेतृत्व ने हमेशा विश्वास किया कि सर्वसत्तावादी विचारधाराओं के खिलाफ लोकतंत्र का प्रसार सबसे प्रमुख हथियार है। फ्रीडम हाउस अपना मिशन विश्व में स्वतंत्रता के प्रसार और यहां घर में मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं को मजबूत करने को स्वीकार करता है। परिणामस्वरूप फ्रीडम हाउस खुले आम युद्धोपरान्त अटलांटिक गठबंधन, और कुछ प्रमुख नीतियों और संस्थाओं जैसे मार्शल प्लान व नाटो का समर्थन करता है। ... ...

''1973 में फ्रीडम हाउस ने अपने मुखपत्र प्रकाशन 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड' का प्रकाशन शुरू किया। जो कि वैश्विक राजनैतिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों का वार्षिक सर्वेक्षण है। ... ...

''जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो फ्रीडम हाउस ने इस विवाद पर सूचना जुटाने के लिए 'अफगानिस्तान इन्फार्मेशन सेण्टर' का गठन किया। पोलैण्ड की 'सालिडरिटी ट्रेड यूनियन' के प्रारम्भिक समर्थकों में से यह एक था। अफ्रीका में बढ़ते विवादों को देखते हुए फ्रीडम हाउस ने बेयार्ड रस्टिन के नेतृत्व में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में अध्ययन मिशन भेजा। 80 के दशक में इसने मध्य अमेरिका में अपने मिशन भेजे जो कि वहां मार्क्सवादी वाम व दक्षिणपंथी हत्यारे गुटों की कैद में चल रहे मध्यमार्गी लोकतांत्रिक ताकतों के समर्थन में था। ... ...

''शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रीडम हाउस के सामने तानाशाहियों की अधीनता वाले समाजों में स्वतंत्रता के प्रसार और नये नाजुक लोकतंत्रों में स्वतंत्र संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने की चुनौती पैदा हुई। ... ... 1997 में 'नेशनल फोरम फाउंडेशन' के साथ विलय से फ्रीडम हाउस की जमीनी कार्यक्रमों को अंजाम देने की क्षमता में वृद्धि हुई और उसने मध्य व पूर्वी यूरोप, बाल्कन और पूर्व सोवियत यूनियन के देशों में लोकतंत्र के प्रसार को आगे बढ़ाया। फ्रीडम हाउस ने पूर्व के कम्युनिस्ट समाजों को स्वतंत्र मीडिया, एन.जी.ओ. थिंकटैंक और चुनावी राजनीति के मुख्य संस्थानों की स्थापना में मदद की। ... ...

''2001 से फ्रीडम हाउस ने दुनिया के कई सबसे कठिन क्षेत्रों में अपने ऑफिस स्थापित करते हुए अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया। ... ...

''फ्रीडम हाउस उन क्षेत्रों में जहां लोकतंत्र का प्रोत्साहन प्राथमिकता है, अमेरिकी विदेश नीति की मजबूत आवाज है। (our history, Freedom house web site)

फ्रीडम हाउस हर वर्ष पूरी दुनिया में स्वतंत्रता–लोकतंत्र की स्थिति की वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है अक्सर ही इसके निशाने पर वे देश होते हैं जो अमेरिका के मन मुताबिक कार्यरत नहीं हैं।

इसके साथ ही दो अन्य प्रमुख संगठन जो अहिंसक उपायों से बदलाव की बातें करते हैं वे हैं– अल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टीट्यूट (AEI) और इंटरनेशनल सेंटर फॉर नॉन वायलैण्ट कान्फिलक्ट (ICNC)। जीन शार्प ए.ई.आई. के वरिष्ठ स्कॉलर हैं। जीन शार्प द्वारा लिखी पुस्तकों को हालिया अरब विद्रोहों की गीता के रूप में प्रचारित किया गया। ए.ई.आई. द्वारा हाऊ टू स्टार्ट ए रेवल्यूशन (How to start a revolution) नामक फिल्म भी प्रसारित की गयी है। इसे अधिकतर फण्ड बड़े कारपोरेट फाउन्डेशनों (मुख्यतः अक्रा फाउन्डेशन) से मिलता है।

इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस द्वारा वित्त पोषित 'यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट फॉर पीस', एन.ई.डी. के ही हिस्से के बतौर कार्यरत 'इण्टरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट' (IRI) व 'नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट' (NDI) (जो अमेरिका की दो प्रमुख पार्टियों से सम्ब(हैं), फोर्ड फॉउण्डेशन, सोरोस द्वारा वित्तपोषित 'न्यू टैक्टिस' व अमेरिकी स्टेट डिपार्टमैन्ट द्वारा वित्तपोषित 'ह्यूमिनिटी इन एक्शन' आदि फाउन्डेशनें लोकतंत्र की प्रमुख पुरोधा हैं।

इसके साथ ही बदनाम ऑटपोर (OTPOR) जो 2003 में कैनवास (centre for Appilied Non Voilent Action & Strategies) में बदल गया था, सीधे ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित करता है। उपरोक्त फंडिग ऐजेन्सियों से सहायता पाने के अलावा यह सी.आई.ए. के घनिष्ठ सहयोग में काम करता है। इसका छात्र आंदोलन 'इंटरनेशनल एक्शन सेन्टर' (IAC) के नाम से मशहूर है। 2000 में सर्बिया में मिलोसेविक के तख्तापलट के साथ ही इसने खासी चर्चा हासिल की। यह 40 से अधिक देशों में ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रहा है। इन सबके साथ यू.एस. एड–USAID (US Agency for international devolopment) है जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की वित्तीय ब्रांच है। आज सुरक्षा–गुप्तचर व रक्षा मामलों में यह अमेरिका की महत्वपूर्ण संस्था बन चुकी है। यह पूरी दुनिया में अमेरिका के आर्थिक व रणनीतिक हितों को संचालित करती है। इसके विभाग संक्रमण पहल (transition initiative), पुनर्निर्माण, टकराव प्रबंधन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र व शासन चलाने की कला (गवर्नेंस) आदि हैं जिनके जरिये लाखों डालर दुनिया भर के राजनैतिक दलों, एन.जी.ओ., छात्र संगठन और उन आंदोलनों को जाते हैं जो अमेरिकी ऐजेण्डे को आगे बढ़ाते हैं। सत्ता पलट हो या रंगीन क्रांति हर परिवर्तन जो अमेरिकी हित में होता है यू.एस.एड वहां डालर बहाता है।

अगर लोकतंत्र के नाम पर कार्यरत इन संगठनों के इतिहास पर नजर डालें तो आज ये पूर्व सोवियत संघ के देशों में गुलाबी क्रांति करने से लेकर वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज के असफल तख्ता पलट तक, रूस में पुतिन के वर्चस्व के खिलाफ, चीन में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, म्यांमार (बर्मा) में सू की से घनिष्ठ सहयोग में, समस्त अरब मुल्कों में, क्यूबा में, थाईलैण्ड में प्रमुखता से सक्रिय हैं। लातिन अमेरिका–अफ्रीका में तो ये लम्बे समय से सक्रिय रहे हैं।

ये संस्थाएं साम्राज्यवाद का हथियार होने के साथ आम जनता के हितों के खिलाफ खड़ी हैं। नव–उदारवादी नीतियों के झण्डे वाला लोकतंत्र कायम करना ही इनका उद्देश्य है। जैसा कि ओबामा की यह स्वीकारोक्ति साबित करती है :

> ''... ... लक्ष्य एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसमें संरक्षणवाद खुलेपन को रास्ता दे, व्यवसाय पर प्रभुत्व एक से कइयों तक पहुंच सके, और अर्थव्यवस्था नौजवानों के लिए रोजगार पैदा कर सके। अमेरिका का लोकतंत्र को समर्थन वित्तीय स्थायित्व, सुधारों को प्रोत्साहन और प्रतियोगी बाजारों के परस्पर व वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण पर आधारित होगा।'' (बराक ओबामा द्वारा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका पर रिमार्क, 19 मई 2011, From Monthly Review, नवम्बर 2011, page -39)

3. 2011 के जन संघर्षों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

अब हम पिछले समयों में हुए संघर्षों में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की चर्चा करेंगे। साथ ही इन संघर्षों मे उनकी भूमिका समझने का प्रयास करेंगे।

इन संघर्षों में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की चर्चा करते हुए हमें इस गलत फहमी का शिकार होने से बचना होगा कि ये संघर्ष इन संगठनों द्वारा रचे–बुने और साम्राज्यवाद द्वारा प्रेरित रंगीन क्रांतियों की तरह के संघर्ष थे। यह सही है कि अधिकांश जगह इन संघर्षों का प्रारंभिक आह्वान साम्राज्यवाद पोषित गैर सरकारी संगठनों ने किया पर इनमें शामिल होकर इतिहास बना देने वाली युवा–मजदूर–मेहनतकश जनता नव–उदारवादी नीतियों और हालिया आर्थिक संकट के चलते बदहाली का शिकार है। इस बदहाली से गुस्सा ही उसे सड़कों पर उतरने की ओर ले गया। अपने अभीष्ट के तौर पर भी इन संघर्षों ने साम्राज्यवाद के हितों को आगे बढ़ाने के बजाय उसे चुनौती देने का ही काम अधिक किया।

अरब विद्रोह

> ''2011 में ट्यूनीशिया, मिश्र और फिर लीबिया में तानाशाहियों के अचानक पतन ने संक्रमण प्रक्रिया के सहयोग के जरूरी मुद्दे को फिर सामने ला दिया और यह इन्डॉवमेंट की प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता बनी हुई है।
>
> ''अगर ट्यूनीशिया जिसका संक्रमण सबसे आगे बढ़ा हुआ है एक सफल अरब लोकतंत्र बन जाता है तो यह अन्य देशों के लिए प्रेरणादायक मॉडल और संभावित समर्थन के लिए आधार बन जायेगा। मिश्र के अरब दुनिया में राजनैतिक प्रभाव और इसके इस क्षेत्र के सबसे अधिक आबादी का देश होने के चलते इसके संक्रमण का भाग्य पूरे मध्य पूर्व के नतीजों को प्रभावित करेगा। गद्दाफी की सत्ता, एक अरब तानाशाही जिसने सब सहारा, अफ्रीका और मध्यपूर्व में बेहद हानिकारक भूमिका निभायी, के पतन ने नागरिक और राजनैतिक ताकतों को एक नये लोकतंत्र की आधारशिला रखने का मौका दिया है।'' (NED Strategy Document, 2012, NED Site)

स्पष्ट है कि मिश्र और ट्यूनीशिया में जनउभार से खासे समय पहले से ही वहां साम्राज्यवादियों द्वारा पोषित एन.जी.ओ. सक्रिय थे। ये लोकतंत्र, मानवाधिकार से लेकर स्त्री स्वातंत्रय की बातों को मुद्दा बनाते रहते थे। ट्यूनीशिया में जहां ये अधिकतर यूरोपीय यूनियन के प्रभाव में संचालित थे तो मिश्र में अमेरिका के।

ट्यूनीशिया के ढेरों नौजवान यूरोपीय देशों में शिक्षा पाते थे इसके साथ देश के भीतर के शिक्षित युवा इन एन.जी.ओ. के प्रमुख आधार क्षेत्र बनते थे। जब मोहम्मद बोआजी द्वारा आत्मदाह किया गया तो इन्हीं शिक्षित युवाओं द्वारा इण्टरनेट के जरिये इस घटना को प्रसारित करने व संघर्ष का आह्वान किया गया।

बेन अली के सत्ता से हटने के बाद राशिद घनौची के नेतृत्व वाली इस्लामिक इन्नहदा चुनाव में भारी जीत दर्ज कर चुकी है। उसकी जीत तमाम एन.जी.ओ. के प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष समर्थन से हुई और वे नव–उदारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिमी साम्राज्यवादियों को पूर्व में ही आश्वस्त कर चुके हैं। अतः ट्यूनीशिया में जन विद्रोह के बाद भी साम्राज्यवादी प्रभुत्व व वर्चस्व बरकरार है। इसीलिए एन.ई.डी. और 'फ्रीडम हाउस' अपने वक्तव्यों में ट्यूनीशिया का लोकतांत्रिक रूपान्तरण पूरा घोषित कर उसे अरब दुनिया के लिए आदर्श के बतौर प्रचारित करने में जुटे हैं :

> ''अमेरिकी सरकार ने उदाहरणतया 100 मिलियन डालर इस वर्ष की शुरुआत में ट्यूनीशिया सरकार को कर्ज अदायगी के लिए दिये साथ ही इन गर्मियों में 300–350 मिलियन डालर के ट्टण का आश्वासन दिया। इससे आगे अमेरिका के ट्यूनीशियाई सत्ता के साथ मदद व सहयोग ने क्रांति उपरांत स्थायित्व व सुरक्षा क्षेत्र सुधार प्रक्रिया में भूमिका निभायी। यूरोपीय दाता भी मुख्य खिलाड़ी रहे। ट्यूनीशिया में अपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की प्रतिबद्धता के साथ ब्रिटिश सरकार ने 170 मिलियन डालर की

नये अरब भागीदारी निधि का वायदा किया जो ट्यूनीशिया सहित मध्य पूर्व में राजनैतिक व आर्थिक सुधारों का समर्थन करेगा। ... ...

''ट्यूनीशिया में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र सहायता प्रदाता यूरोपीय यूनियन, अमेरिकी सरकार के विभिन्न विभाग (MEPI,OTI सहित), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और कुछ हद तक विभिन्न विदेशी दूतावास है। इन सरकारी खिलाड़ियों के अतिरिक्त लोकतंत्र सहायता के पेशेवर क्षेत्र में लगे कई अंतर्राष्ट्रीय एन.जी.ओ., जिन्हें मैं लोकतंत्र संस्थान कहता हूं, के ऑफिस ट्यूनीशिया में खुल चुके हैं। इनमें कार्टर सेन्टर, ई.आर.आई.एस. (ERIS), फ्रीडम हाउस,आई.एफ.ई.एस. (IFES), इण्टरनेशनल रिपब्लिकिन इंस्ट्टीट्यूट, कोनार्ड एडेनाउट स्टिफटंग नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्ट्टीट्यूट, और सर्च फार कॉमन ग्राउण्ड शामिल हैं।''(Democracy Promotion after the jasmine Revolutions : A Dispatch From Tunis by Sarah Bush : http:/k/kapp.reads speaker.com)

मिश्र में भी साम्राज्यवाद पोषित गैर सरकारी संगठनों की लम्बे समय से मौजूदगी रही है। तहरीर चौक पर 25 जनवरी के प्रदर्शन का आह्वान करने वाला संगठन 'अप्रैल 6 यूथ मूवमेंट' था। इसका प्रमुख संगठनकर्ता अहमद माहेर (30 वर्षीय सिविल इंजिनयर) शुरू में किफाया (kefaya अर्थात पर्याप्त) संगठन में सक्रिय था। इससे 2005 में अलग होकर माहेर व उसके साथियों ने अपना अलग यूथ ब्रिगेड 'यूथ फार चेंज' बनाया परन्तु उसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला साथ ही कई नेता गिरफतार भी हो गये।

23 मार्च 2008 को इन्होंने अप्रैल.6 यूथ मूवमेंट के नाम से एक वेब पेज बनाकर माहला में कम वेतन व खाद्यान्न के महंगे दाम के खिलाफ हड़ताल कर रहे टेक्सटाइल मजदूरों के समर्थन का आह्वान किया। इस पेज को कुछ हफतों में ही 70000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। 6 अप्रैल को प्रदर्शन के इसके आह्वान पर हजारों मजदूर इकट्ठा हो गये। प्रदर्शन का पुलिस ने दमन किया। चार लोग मारे गये व 400 गिरफतार हो गये।

इसके बाद 4 मई 2008 को मुबारक के 80 वें जन्म दिन पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया जो असफल रहा। माहेर को गिरफतार कर लिया गया।

अप्रैल 6 यूथ मूवमेंट के लोगों ने अहिंसक प्रदर्शनों की ट्रेनिग सर्बिया में ऑटपोर (OTPOR) से ली। वहां मिलोसेविक के तख्तापलट से इन्होंने सीख ग्रहण की। 2008 में इसके सदस्य अमेरिका जाकर 'एलांइस ऑफ यूथ मूवमेंट समिट' में शामिल हुए जो कि अमेरिकी सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित था।

अमेरिकी डेमोक्रेसी संस्थानों से पोषित और प्रशिक्षित इसके कार्यकर्ताओं ने बेन अली की रुखसती से प्रभावित हो 25 जनवरी 2011 को विरोध प्रदर्शन की तिथि तय की क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था। इसके लिए एक ऑपरेशन रूम बनाया गया जहां से वेबसाइट के जरिये प्रदर्शन का आह्वान किया जाता था। दो दिन पूर्व ग्रुप ने 30–50 लोगों के ढेरों सेल बनाये। जिन्हें काहिरा के अलग अलग जगह एकत्र होना था लेकिन हर सेल में एक व्यक्ति को ही जुलूस का नेतृत्व दे उसे मुख्य प्रदर्शन स्थल तक ले जाना था। इसके साथ ही असामा माहफोज (Asmaa MahFouz) नामक युवती जो कि संगठन की संस्थापकों में से एक थी ने एक विडियो जारी कर लोगों से सरकार से न डरते हुए प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। इस विडियो का असर देशव्यापी हुआ।

अन्य ग्रुपों में फ्वी आर ऑल खालिद सईद (we are all Khaled Said)'' फेस बुक पेज अस्तित्व में आया। जिसे गूगल के अधिकारी वेल घोनिम (wael Ghonim) ने जून 2010 में बनाया था खालिद सईद की पुलिस ने पीट कर हत्या कर दी थी। जून मध्य 2010 तक इसके 1,30000 सदस्य बन गये जो 22 जनवरी 2011 तक बढ़कर तीन लाख 80 हजार जा पहुंचे। इस तरह यह मिश्र का सबसे बड़ा ऑन लाइन मानवाधिकार ग्रुप बन गया। 25 जनवरी प्रदर्शन के दौरान घोनिम को कैद में रख लिया गया जिन्हें बाद में रिहा किया गया।

इसके साथ ही मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक भी तहरीर चौक में शामिल थे। पश्चिम समर्थक अल–बरदेई का विरोध आंदोलन तो था ही। इन सबने व अन्य संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से 'रिवोल्यूशनरी यूथ कांउसिल' का गठन किया था और 11 फरवरी को मुबारक की रुखसती के बाद आजाद मिश्र का जन्म सर्टिर्फिकेट जारी किया था।

14 फरवरी को अहमद माहेर ने अपने सदस्यों को प्रदर्शन जारी न रखने का आह्वान करते हुए कहा ''जो प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं उनके अपने मुद्दे हैं। हमने प्रदर्शन न करने का निर्णय लिया है। हाल फिलहाल हम अपनी मांगों पर निर्णय का इंतजार करेंगे। हम कभी भी सड़कों पर दुबारा जा सकते हैं।'' ध्यान देने की बात है यह वही समय था जब मजदूर प्रदर्शन जारी रख विद्रोह आगे बढ़ाना चाहते थे।

'अप्रैल 6 मूवमेंट' अपनी कोई विचारधारा घोषित नहीं करता है। यह पश्चिम समर्थक अल–बरदेई को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने तक को तैयार हो गया। हालांकि अल–बरदेई को ब्रदरहुड के ही लोगों द्वारा पश्चिमी एजेंट करार देने से वह दौड़ से बाहर हो गया।

मुबारक की रुखसती के बाद सत्ता सेना के नियंत्रण में आ गई। उसने नये संविधान की मांग को दरकिनार कर संसद व राष्ट्रपति के चुनाव 2013 तक कराने का निर्णय लिया। मुबारक के प्रधानमंत्री अहमद शफीक पर प्रदर्शनकारियों ने हटने का दबाव बना संसद द्वारा 10 वर्ष का राजनैतिक प्रतिबंध लगवा दिया था। एक वर्ष बीतते बीतते स्थितियों ने एक दम भिन्न मोड़ ले लिया। मिश्र की सेना में व बाहर मुबारक समर्थकों ने पुनः सत्ता हासिल करने के प्रयास शुरू कर दिये। तमाम प्रदर्शनकारियों के हत्यारे पुलिस वालों को अदालतें रिहा करने लगी। मुबारक के दो पुत्रों, 6 वरिष्ठ अफसरों को रिहा कर दिया गया। भ्रष्टाचार में मुकदमे से मुबारक को बरी व प्रदर्शनकारियों के दमन के मामले में उम्र कैद की सजा दे दी गई। हालांकि 2 पुत्रों को जनदबाव के चलते अभी एक अन्य मुकदमे के तहत जेल में रखा गया है। अहमद शफीक को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की छूट दे दी गयी। आश्चर्यजनक रूप से उसने पहले राउण्ड में 24 प्रतिशत मतों के साथ मुस्लिम ब्रदरहुड प्रत्याशी के बाद दूसरा स्थान हासिल कर लिया। दूसरे राउण्ड का मतदान 16.17 जून को संपन्न हो गया। इस बात की संभावना रखी गयी थी कि शफीक के जीतने पर मुबारक को बरी कर दिया जाय। इस बीच 15 जून को कोर्ट द्वारा चुनी हुई संसद को भंग कर दिया गया और राष्ट्रपति चुनावों में मुस्लिम ब्रदरहुड के जीतने की आशंका में सेना ने नयी घोषणायें करते हुए चयनित संस्थाओं के अधिकार सीमित व अपने अधिकारों में वृद्धि कर दी। अंततः सेना व ब्रदरहुड के बीच गुप्त समझौता होने के बाद ब्रदरहुड प्रत्याशी मुर्सी की जीत की घोषणा कर दी गयी। मिश्र में सत्ता संघर्ष जटिल रूप से उलझ चुका है अमेरिकी साम्राज्यवादी इसमें अब भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पु

इसके साथ 2011 का अंत आते आते सेना ने साम्राज्यवाद पोषित गैर सरकारी संगठनों पर लगाम कसनी शुरू कर दी थी। एन.ई.डी.ए फ्रीडम हाउस समेत 10 एन.जी.ओ. के दफतर सीज कर दिये गये। अप्रैल 6 आंदोलन को मुबारक समर्थकों व सैन्य अधिकारियों द्वारा पश्चिम पोषित करार कर उसे जनता से अलगाव में डालने के प्रयास किये जाने लगे। क्रांति को आगे बढ़ाने वाली अन्य जनपक्षधर क्रांतिकारी ताकतों, मजदूर यूनियनों पर तो 18 दिन के जमावड़े के बाद से ही शिकंजा कसा जा रहा था।

'अप्रैल 6 मूवमेंट' ने अब अपनी रक्षा में अना अब्रिली (मैं अप्रैल 6 हूँ) व एक्टेब दस्तोराक (अपना संविधान लिखो) अभियान शुरू किये हैं। इसके साथ ही अप्रैल 6 मूवमेंट ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर मुबारक ने मुकदमे की दुबारा सुनवाई व अहमद शफीक की उम्मीद्वारी रद्द करने की मांग को प्रदर्शन शुरू कर दिये। साथ ही यह शफीक को हराने के लिए ब्रदरहुड प्रत्याशी मोहम्मद मुर्सी के

समर्थन में समस्त विपक्ष को एकजुट करने लग गया। अमेरिकी फाउंडेशनों व स्वयं सेवी संगठनों पर जब सेना ने छापे डालने शुरू कर दिये तो फ्रीडम हाउस के अध्यक्ष ने अमेरिकी स्टेट्स हाउस कमेटी ऑन फारेन अफेयर्स के सामने प्रस्तुत हो हस्तक्षेप की मांग की :

''मैडम चेयरवुमेन, कमेटी के सदस्यो, यहां आपके सामने उपस्थित होकर मिश्र के हालिया विकास क्रम पर चर्चा करना सम्मान का विषय है। मैं अपने सहयोगियों केन वोलाक, लोरन कार्नर और ज्यासी बर्नाथन, जो एन.डी.आई., आई.आर.आई. व आई.सी.एफ.जे. से सम्बन्धित हैं, के साथ प्रस्तुत होकर खुश हूं।

... ...

''हमारा संगठन और स्टाफ एक बार मुख्य खबरों में था लेकिन हमें उन सैकड़ों मिश्र के गैर सरकारी संगठनों को नहीं भूलना चाहिए जो इसी तरह का दबाव व आरोप झेल रहे हैं। जिनके पास कोई अमेरिकी कार्यरत नहीं है। 29 दिसम्बर को जिन 10 संगठनों पर मिश्र की सेना ने छापा मारा उनमें 5 विदेशी थे (हमारे 4 संगठन और कोनार्ड एडिनाइट फाउंडेशन) और 5 मिश्र के थे। कुल 17 ऑफिसों पर छापा मारा गया। इसके अतिरिक्त करीब 400 मिश्र के एन.जी.ओ. सरकार की जांच और बेरहम दबाव का सामना कर रहे है।

... ...

''अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर अमेरिका को मिश्र के प्रशासकों द्वारा मानवाधिकारों के हनन और सिविल सोसाइटी से किये व्यवहार पर आक्रामक प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अमेरिका की मिश्र को मदद– जो केवल सैन्य मामलों में ही 1.3 बिलियन डालर, मिश्र के सैन्य बजट के पांचवे हिस्से के बराबर है–प्रशासन के अमेरिकी कांग्रेस के सामने यह सुनिश्चित करने पर कि मिश्र की सरकार नागरिक सरकार की ओर कदम बढ़ा रही है और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जा रही है, निर्भर करती है। हालिया विकासक्रम इस तरह की बात सुनिश्चित करना असम्भव बना रहा है। यह समझना कठिन है कि कैसे अमेरिका कर दाताओं से प्राप्त राशि को उन मिश्र की सेना के नेतृत्व को दे सकता है जो उन एन.जी.ओ.को लोकतंत्र की स्थापना व मानवाधिकार परियोजनाओं पर काम करने से रोकती है जिन्हें अमेरिकी कर दाताओं का समर्थन प्राप्त है। ... ...

''राष्ट्रपति बराक ओबामा, कई कांग्रेस सदस्यों सहित वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने अपने मिश्र के प्रतिपक्षियों से मिश्र के अधिकारियों का रुख बदलने की बात की है पर अभी तक सफल नहीं हुए हैं। मेरा विश्वास है कि केवल अमेरिका का सैन्य सहायता निलम्बित करना ही मिश्र की सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकता है।

''... ... ... यह अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि सिविल सोसाइटी और अमेरिका द्वारा वित्त पोषित एन.जी.ओ. पर हमला बगैर गम्भीर कीमत चुकाये नहीं किया जा सकता।''

(Testimony of David J Kramer, President of Freedom House Before the US House Committee on Foreign Affairs, Egypt at a Crossroads 16 Feb 2012, From Freedom House Site)

साम्राज्यवाद द्वारा पोषित एन.जी.ओ. लीबिया व सीरिया में भी वर्षों से कार्यरत रहे हैं परन्तु अधिकतर ही उन्हें छिपे रूप में ही काम करना पड़ता रहा है। क्योंकि अक्सर ही ये वहां की सत्ता के खिलाफ लोगों को भड़काने, सत्ता को अस्थिर करने में जुटे रहते थे। गद्दाफी व बशर अल असद के खिलाफ साम्राज्यवादियों की निगाहें पहले से टेढ़ी रही हैं। जब ट्यूनीशिया–मिश्र के साथ यहां भी कुछ प्रारम्भिक प्रदर्शन शुरू हुए तो साम्राज्यवादियों ने इसे एक अवसर के तौर पर भुनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। दोनों ही जगहों पर साम्राज्यवादियों द्वारा प्रशिक्षित विद्रोहियों की काउंसिल कायम कर दी गयी। हथियारबंद काउंसिल के नेता सी.आई.ए. से नजदीकी रूप से सम्बद्ध रहे हैं। लीबिया में विद्रोहियों व लीबियाई सेना के बीच युद्ध में नागरिकों के मारे जाने के मुद्दे को बहाना बना फ्रांस–इंग्लैण्ड–अमेरिका ने लीबिया पर हमला बोल दिया। गद्दाफी की हत्या के बाद पश्चिम परस्त तेल व्यवसायी वहां की सत्ता पर काबिज हैं। सीरिया में भी साम्राज्यवादी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहां तो विद्रोहियों द्वारा जबरन नागरिकों की हत्या को मीडिया द्वारा असद द्वारा नागरिक हत्या प्रचारित कर उस पर दबाव बनाया जा रहा है। समूचे पश्चिमी मीडिया के साथ कतर स्थित अल–जजीरा भी इस अभियान में जुटा है।

इन दोनों जगह ही कार्यरत एन.जी.ओ. मुख्यतः विद्रोही तैयार करने में जुटे हैं। इनके साथ ही अल कायदा से लेकर अन्य आतंकी भी अमेरिका के साथ सहयोग कर रहे हैं। अल कायदा के लोगों का लीबिया में अमेरिकी सहयोग में काम करना एक बार फिर यह हकीकत बयां कर देता है कि अलकायदा को सी.आई.ए. द्वारा ही पैदा प्रशिक्षित किया गया था। और आतंक के खिलाफ युद्ध के अमरीकी नारे का अर्थ अमरीकी जरूरत के मुताबिक अफगानिस्तान व लीबिया में अलग–अलग है। यमन, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरब सरीखी तानाशाही वाले राष्ट्रों में भी लोकतंत्र प्रसार के एन.जी.ओ. सक्रिय हैं। फिलहाल अमेरिकी साम्राज्यवादी जरूरतों के मद्देनजर कोई बड़ी पहलकदमी लेने या सत्ता पलटने के बजाय इन देशों की सरकारों के साथ सहयोग करते हुए कुछ सुधारों की मांग तक ही जनता को सीमित रखने में संलग्न हैं। यमन बहरीन में जनता की व्यापक स्वतःस्फूर्त पहलकदमी तुलना में अधिक थी। यमन में सलेह सत्ता से स्वतः ही हट चुका है तो बहरीन में गल्फ कोआपरेशन काउंसिल की संयुक्त सेना के दम पर विद्रोह कुचल दिया गया।

इस तरह देखा जाय तो साम्राज्यवाद परस्त एन.जी.ओ. समूचे अरब में कार्यरत हैं। बहुत सारे लोगों ने मिश्र–ट्यूनीशिया के जनविद्रोहों को जॉर्जिया सरीखी रंगीन क्रांति या साम्राज्यवाद प्रेरित क्रांति कहना शुरू कर दिया है। परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। गैर सरकारी संस्थाओं के अलावा इन देशों में जनविद्रोह में पूंजीवादी संगठन, ट्रेड यूनियनों से लेकर क्रांतिकारी समूह तक भागीदारी कर रहे थे जो अपने–अपने वर्गीय हितों के मद्देनजर जनविद्रोह को अलग–अलग मंजिल तक ले जाना चाहते थे। मिश्र में यह टकराहट अभी भी जारी है। ऐसे में साम्राज्यवादी गैर सरकारी संस्थाओं के जरिये अपने हितों को सुरक्षित करने में जुटे हैं। नीचे दी तालिका अमेरिका द्वारा अरब देशों में दी सैन्य व डेमोक्रेसी फण्ड के अनुपात को दिखाती है।

(ratio between U S Milltary aid &Democracy aid)

अमेरिका की सैन्य व लोकतंत्र सहायता का अनुपात

देश	अनुपात
बहरीन	258.52
ओमान	245.17
मोरक्को	102.95
जार्डन	73.04
मिश्र	65.16
ट्यूनीशिया	16.44
यमन	6.66

(स्रोत : The Arab revolts and the cage of Political economy by Benoit Challand)

साम्राज्यवाद के निशाने पर अरब के सीरिया व कुछ हद तक लीबिया ही पहले से रहे हैं। बाकि शेखशाहियां व तानाशाहियां साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित व पोषित रही हैं। ऐसे में मिश्र–ट्यूनीशिया में सत्ता परिवर्तन की साम्राज्यवादियों को तत्काल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी अगर यह आवश्यकता होती तो सैन्य मदद 'डेमोक्रेसी फण्ड' से कई गुना अधिक न होती।

दरअसल साम्राज्यवादी इन सभी तानाशाहियों को पालते पोसते हुए भी इस हकीकत से वाकिफ थे कि एक न एक दिन जनता इनके खिलाफ उठ खड़ी होगी। ऐसी स्थिति में जनउभार कहीं उनकी पालित तानाशाहियों को हटाते हुए साम्राज्यवाद विरोधी सत्ता न कायम कर ले, इसके इंतजाम के बतौर साम्राज्यवादी इन सभी देशों में इन सत्ताओं के विरोधियों को लोकतंत्र स्थापना के नाम पर पालते पोषते रहे हैं। सामान्य स्थितियों में इन विरोधियों द्वारा लोकतंत्र के नाम पर किया हल्ला साम्राज्यवाद को इन तानाशाहियों पर लगाम रखने में मदद करता रहा है परन्तु इससे ज्यादा इनकी भूमिका तब है जब वास्तव में जन उभार पैदा हो जाये और दमन से भी न कुचला जा सके। तब वह जन उभार सत्ता में मामूली परिवर्तन के साथ शांत हो जाय इसके इंतजाम के बतौर साम्राज्यवादी तानाशाहियों के विरोधी लोगों को पालते रहे हैं। इस रूप में ये गैर सरकारी संगठन साम्राज्यवाद की दूसरी रक्षा पंक्ति का काम करते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि तानाशाही समाप्त भी हो जाये तो भी साम्राज्यवादी हित सुनिश्चित रहें। समूचे अरब में जनता साम्राज्यवाद प्रेरित नव–उदारवादी नीतियों के साथ हालिया मंदी की मार से परेशान बेहाल थी। बेरोजगारी की आसमान छूती दर, कम मजदूरी, शासकों के निर्लज्ज भ्रष्टाचार ने उसके आक्रोश को अरब विद्रोह के रूप में अभिव्यक्त किया। चूंकि इन देशों में तानाशाही होने के चलते विरोध प्रदर्शनों की विशेष गुंजाइश नहीं थी इसलिए ये आक्रोश एक झटके के साथ ट्यूनीशिया से शुरू हो मिश्र, बहरीन,यमन, सऊदी अरब व अन्य देशों तक जा पहुंचा। एक सैलाब के साथ पैदा हुए इस आक्रोश ने तानाशाहियों को अपने निशाने पर लिया। तानाशाहियां और उनके आका साम्राज्यवादी हैरान परेशान हो गये। पहले तो उन्होंने ट्यूनीशिया–मिश्र में विद्रोह को कुचलने के प्रयास किये परन्तु आक्रोश ठंडा न होता देख उन्होंने अपने गैर सरकारी संगठनों की मदद से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि एक दो व्यक्तियों के बदलाव तक ही चीजें सीमित हो जायें और उनका वर्चस्व कायम रहे।

ट्यूनीशिया में उनका यह कार्य खासी आसानी से हो गया परन्तु मिश्र में उनके द्वारा आगे बढ़ाया अल–बरदेई खुद आंदोलन के मध्य से पश्चिमी एजेंट करार दिया जाकर बदनाम हो नेपथ्य में चला गया। इस बीच मजदूरों की पहलकदमी निरंतर जारी रही हैं। यह मजदूरों की व्यापक हड़तालें ही थीं जिन्होंने मुबारक की रुखसती को मुकाम तक पहुंचाया था। ऐसे में सत्ता के सूत्र अपने हाथ में रखने के लिए साम्राज्यवादियों पर दो ही रास्ते थे पहला कट्टरपंथी मुस्लिम ब्रदरहुड को आगे करना दूसरा मुबारक समर्थकों को दुबारा सत्ता में आगे आने का मौका देना। साम्राज्यवादियों ने इन दोनों ही विकल्पों पर जोर आजमाइश शुरू कर दी ताकि कोई अंवाछित तीसरा विकल्प पैदा न हो सके। मुबारक समर्थक सैन्य अधिकारियों ने इसके लिए अमेरिकी फाउण्डेशनों, अप्रैल 6 मूवमेंट का दमन तक किया। परन्तु अमेरिका के लिए अपने हित अधिक महत्वपूर्ण है बजाय कुछ गैर सरकारी संगठनों के दमन के। हां अमेरिका ने सेना द्वारा गिरफतार सभी अमरीकियों को जरूर रिहा करवा सुरक्षित कर दिया। मिश्र के घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र के अमेरिकी मॉडल का मतलब पूर्व में उद्धृत ओबामा की स्वीकारोक्ति ही है। मिश्र में यह अभी भविष्य के गर्भ में है कि स्थिति किस ओर आगे बढ़ती है।

मिश्र–ट्यूनीशिया में भले ही साम्राज्यवादी दमन में कामयाब न हुए हों पर बहरीन–यमन में उन्होंने दमन के जरिये संघर्ष कमजोर करने में कुछ हद तक सफलता जरूर पा ली। हालांकि यमन में सालेह की रुखसती भी हो गयी। बहरीन अमेरिकी सैन्य बेड़े की वजह से महत्वपूर्ण था इसलिए अमेरिका यहां कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। परिणामतः संघर्ष का सबसे बर्बर दमन यहीं किया गया। इसी तरह ओमान, कतर, सऊदी अरब में संघर्ष शुरुआत में ही कुचल दिये गये।

लीबिया–सीरिया में साम्राज्यवादियों ने एकदम भिन्न नीति अख्तियार कर वहां जन विद्रोह को बहाने के बतौर इस्तेमाल कर वहां अपनी समर्थक सत्ता बैठाने की नीति अपनाई। लीबिया में साम्राज्यवादी कब्जे में सफल हो चुके हैं। सीरिया को घेरने के प्रयास जारी है।

इन जन विद्रोहों के वक्त साम्राज्यवादी मीडिया ने बढ़ चढ़ कर साम्राज्यवाद के पक्ष में भूमिका निभाई। कतर के अमीर की देख–रेख में चल रहा अल–जजीरा भी इसमें शामिल रहा। अल–जजीरा ने जहां ट्यूनीशिया–मिश्र के प्रदर्शनों की कवरेज कर प्रसिद्धि पायी वहीं लीबिया और सीरिया में जनता के दमन, व्यापक प्रदर्शनों की झूठी खबरें तक प्रसारित करने से वह बाज नहीं आया। हालांकि ट्यूनीशिया–मिश्र में भी बेन अली–मुबारक की रुखसती के बाद हुए प्रदर्शनों को उसने कम ही संज्ञान में लिया। यह साम्राज्यवाद की नीति के अनुरूप ही था।

फिर भी अरब विद्रोह ने साम्राज्यवादी शासकों के चेहरों पर कॅपकॅपी जरूर पैदा कर दी। यह कॅपकॅपी तब और बढ़ गयी जब विरोध की यह लहर यूरोप और अमेरिका जा पहुंची।

यूरोप और अमेरिका के विरोध प्रदर्शन

अरब में जब विद्रोह फूट पड़ा तो साम्राज्यवादियों ने प्रचारित करना शुरू किया कि ये जनवाद के लिए संघर्ष है परन्तु जब संघर्ष फैलता हुआ यूरोप में इंडिग्नोस आंदोलन व अमेरिका में 'आक्यूपाई वाल स्ट्रीट' के रूप में छाने लग गया तो साम्राज्यवादियों के माथे पर पसीना छलक आना स्वभाविक ही था। उनके लिए अगर कोई बात सकून की थी तो वो यह कि इन आंदोलनों में भी नेतृत्वकारी भूमिका ढेरों गैर सरकारी संगठनों की थी। ये नस्ल भेद, पर्यावरण, स्त्री मुक्ति, यूथ आंदोलन से लेकर भांति–भांति पहचानों के लिए संघर्षरत संगठन थे जिन्होंने इन आंदोलनों में पहलकदमी ले जनाक्रोश को पूंजीवादी दायरे में समेटने का काम किया।

भांति–भांति की पहचानों वाले इन संगठनों के यूरोप में बड़े पैमाने के प्रदर्शन मई–जून 2011 में हुए। इन्हें इंडिग्नोस आंदोलन के रूप में जाना गया। इन्होंने अपना लक्ष्य असली जनतंत्र घोषित किया। वर्तमान जनतंत्र को बैंकपतियों व भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का जनतंत्र करार देते हुए जनता के असली जनतंत्र का नारा दिया। यूरोप व्यापी कटौती कार्यक्रमों (ऑस्टेरिटी) कदमों का इसने विरोध किया।

असली जनतंत्र का नारा ही इस आंदोलन की सीमाएं स्पष्ट कर देता है राजनीति से दूर रहने की बात करने वाले इस आंदोलन के नियंताओं में पूंजीवादी जनतंत्र के बरक्स समाजवाद का नारा बुलंद करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

अमेरिका में शुरू हुए 'आक्यूपाई वाल स्ट्रीट' आंदोलन में भी शुरुआती पहलकदमी गैर सरकारी संगठनों द्वारा ही ली गयी। मध्य जुलाई 2011 में 'एडबस्टर्स मीडिया फाउण्डेशन' ने प्रारम्भिक आह्वान किया और एक पोस्टर जारी किया। एडबस्टर्स खुद को नॉन प्राफिट ''उपभोक्तावाद विरोधी'' संगठन बताता है जो कि कलाकारों कार्यकर्ताओं, लेखकों, छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों के वैश्विक नेटवर्क की तरह काम करता है और सूचना युग के नये सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता है।

एडबस्टर्स बहुराष्ट्रीय फाउण्डेशनों द्वारा समर्थित रहा है। यह ढेरों प्रगतिशील समझी जाने वाली फाउण्डेशनों, जिसमें 'बिग काहुना ऑफ लेफिटश फाउन्डेशन', 'द टाइड्स फाउण्डेशन' व 'टाइड्स सेण्टर' शामिल हैं, से पैसा लेता है। टाइड्स ने एडबस्टर्स को 1996–2003 के दौरान 334,217 डॉलर का अनुदान दिया।

टाइड फाउण्डेशन अन्य दाताओं से पैसा लेकर उन्हें 'वाम' संगठनों को हस्तांतरित करता है जिन्हें वास्तविक दाता खुद सीधे दान नहीं करना चाहते। इसको मिलने वाला दान पूर्णतः गुप्त होता है। जॉर्ज सोरोस सरीखे लोग इसे पैसा देते रहे हैं। अन्य गैर सरकारी संगठनों ने जिन्होंने शुरुआत में ही पहलकदमी ली वे थे 'यू .एस.डे ऑफ रेज' (US Day of Rage) जो कि मुख्यतः इण्टरनेट आधारित संगठन है, 'एनोनिमस' (Anonymous) जिसे इण्टरनेट हैकरों का संगठन भी कहा जाता है, जार्ज सोरोस 'यू.एस.डे ऑफ रेज' (US Day of Rage) से 'दि रकस सोसायटी' (The Ruckus Society) के जरिये सम्बद्ध है। रकस सोसायटी भी टाइड फाउण्डेशन से पैसा पाती है और सोरोस की ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ने टाइड्स को अकेले 2008 में 4.2 मिलियन डॉलर अनुदान दिया।

जहां एडबस्टर्स ने 'यू.एस.डे ऑफ रेज' और 'एनोनिमस' के साथ मिलकर इण्टरनेट पर आंदोलन का शुरुआती आह्वान किया वहीं जमीनी स्तर पर एक ग्रुप 'न्यूयार्कर्स अगेंस्ट बजट कट्स' (New Yorkers Against Budget Cuts) ने जून जुलाई में ''न्यूयार्क जनरल असेम्बली'' के जरिये ऑस्टेरिटी का विरोध किया। न्यूयार्क जरनल असेम्बली में धीरे–धीरे ढेरों संगठन, कलाकार, छात्र, यूनियन वर्कर शामिल हो गये। इनमें शामिल लोग अलग अलग विचारधारा लिये लोग थे। जनरल असेम्बली ही बाद में इस आंदोलन की निर्णय लेने वाली निकाय कही गयी। इसमें गैर सरकारी संस्थायें, छात्र, यूनियन वर्कर से लेकर अराजकतावादी–कम्युनिस्ट सभी शामिल थे।

17 सितम्बर को जुकौती पार्क पर प्रदर्शन से पूर्व इन्होंने कई जगह असेम्बली स्थापित कर पूर्व तैयारी की थी। 17 सितम्बर के बाद ये असेम्बली देश के ढेरों अन्य शहरों में भी आयोजित होने लग गईं।

जनरल असेम्बली को नेतृत्व विहीन, आम राय आधारित सिस्टम कहा गया जिसमें ढेरों मतों के लोग बहस के जरिये सहमति तक पहुंच सकते थे। अराजकतावादी विचारों से प्रभावित यह जनरल असेम्बली हालांकि इतनी भी नेतृत्व विहीन नहीं थी। कुछ मुख्य आयोजक संगठनों का उस पर पूर्ण नियंत्रण था। पर इन आयोजक समूहों में भी ढेरों विवाद थे। जिसमें प्रमुख था कि आंदोलन की मांगें सूत्रित की जायें या नहीं। एडबस्टर्स सरीखी संस्थायें जहां इस बहाने कि पहले आंदोलन विस्तारित कर लिया जाय तब मांगे सूत्रित की जायें क्योंकि मांगे पहले सूत्रित करने से इसका जनाधार बढ़ने की संभावना सीमित कर देंगे, कोई मांग सूत्रित नहीं कराना चाहते थे तो ढेरों अन्य वामपंथी संगठन इसकी मांगें सूत्रित करना चाहते थे।

कॉरपोरेट पूंजीपतियों–सोरोस–बफेट ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और इसके जरिये ओबामा सरकार पर पूंजीपतियों पर ज्यादा टैक्स लगाने, कटौती कार्यक्रम रोकने की वकालत की।

यह आंदोलन अभी भी जारी है। हालांकि जुकौती पार्क का जमावड़ा 2011 के अंत आते–आते समाप्त हो गया। इसके आयोजकों ने 2014 तक प्रदर्शनों का कार्यक्रम सूत्रित कर लिया है। अपने लक्ष्यों के लिए 'न्यूयॉर्क जनरल असेम्बली' जो घोषित करती है वह इस प्रकार है :

> ''एक एक्यबद्ध जनता के बल पर हम इस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं कि मानव जाति का भविष्य अपने सदस्यों से सहकार की मांग करता है, कि हमारी व्यवस्था को हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और इस व्यवस्था के भ्रष्ट होने पर यह व्यक्तियों पर है कि वे अपने अधिकारों और अपने पड़ोसियों के अधिकारों की रक्षा करें, कि कोई जनतांत्रिक सरकार खुद अपनी जनता से शक्ति ग्रहण करती है लेकिन निगम जनता व पृथ्वी से सम्पदा के दोहन हेतु सहमति नहीं लेते। ऐसे समय में ऐसे में कोई सही जनतंत्र उस समय तक नहीं हासिल किया जा सकता जब तक आर्थिक शक्ति द्वारा प्रक्रिया निर्धारित होती है। हम ऐसे समय में आपके पास आये हैं जब निगम हमारी सरकारें चला रहे हैं, जो जनता के ऊपर मुनाफे को रखते हैं, न्याय से ऊपर खुद के स्वार्थ को रखते हैं और समानता के ऊपर दमन को रखते हैं। हम यहां शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यह हमारा अधिकार बनता है कि 'न्यूयॉर्क शहर के दखल की घोषणा' के ये तथ्य जाने जायें। (occupy wall street : leading from behind by William Bowles)

अरब क्रांतियों की तरह इंडिग्नोस व आक्यूपाई आंदोलनों को भी साम्राज्यवाद प्रायोजित संघर्ष नहीं करार दिया जा सकता बल्कि ये भी नव–उदारवादी नीतियों–आर्थिक मंदी की मार के खिलाफ जन आक्रोश था जिसे गैर सरकारी संस्थायें व्यवस्था के दायरे में समेटने के प्रयास में डटी रही हैं।

इसी तरह ये गैर सरकारी संस्थायें रूस में पुतिन विरोधी प्रदर्शनों, इस्राइल के तम्बू गाड़ो आंदोलन में भी सक्रिय थीं।

4. कुछ बातें भारत के अन्ना आंदोलन पर

भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन एक अर्थों में 2011 के आंदोलनों का हिस्सा होते हुए भी उसकी विच्युत्ति अधिक था। अरब विद्रोह–इंडिग्नोस –आक्यूपाई के विपरीत यह पूर्णतः कारपोरेट जगत, मीडिया जगत, एन.जी.ओ. द्वारा प्रायोजित आंदोलन था। जहां पहले के आंदोलनों ने पूंजीपति वर्ग, साम्राज्यवादियों के लिए मुश्किलें पैदा कीं वहीं इस आंदोलन का लक्ष्य ही पूंजीपति वर्ग के हितों को आगे बढ़ाने वाला था। जैसा की ई.पी.डब्लू के अपने लेख में रविन्दर कौर सूत्रित करती हैं :

> '' ... ... तब मुख्य सवाल पूछा जाना जरूरी है कि भ्रष्टाचार भारतीय राष्ट्र के समक्ष कैसे और कब सबसे महत्वपूर्ण संकट हो गया और राष्ट्र की नैतिक सफाई की इस परियोजना से किसके हित प्रभावित हुए हैं। खोजबीन की यह दिशा कुछ तात्कालिक जवाबों का रास्ता खोलती है जो ऐसे आंदोलन की व्याख्या करने में मदद करते हैं जिसमें तकनीकी अभिजात, पेशेवर मध्यम वर्ग, शहरी गरीब, धार्मिक और निरपेक्ष किस्म के व्यक्ति, बड़े निगम, वैश्विक गैर सरकारी संगठन और स्थानीय मोहल्लों की एसोसिएशन जैसे विविध हित सफलतापूर्वक गठबंधन बना चुके हैं। इस सम्बंध में भारतीय सामाजिक राजनैतिक परिदृश्य के भीतर तीन महत्वपूर्ण अन्तरसंबंधित विकास क्रमों को पहले से ध्यान में रखा जा सकता है। पहला राष्ट्र रूप की नव–उदारवादी धारणा को माल रूप में देखने की जिसमें भारत 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से पहले से ही रूपान्तरित हो चुका है अब राष्ट्र की योग्यता को इसके द्वारा क्षेत्र हासिल करने की और अपने जनता के कल्याण करने की योग्यता से ही मुख्यतया नहीं आंका जाता है बल्कि पूंजी निवेश को आकर्षित करने और राजस्व को अधिकाधिक करने की इसकी योग्यता से नापा जाता है। भारतीय राष्ट्र ने नयी नामावली 'इंडिया इनकारपोरेटेड' अपना लिया है जो निगमित घरानों और नीति निर्माताओं के घेरे के भीतर व्यापक रूप से लोकप्रिय है। 'इनकारपोरेटेड' विशेषण का जुड़ना राष्ट्र के निगमित चरित्र को उजागर करता है जो पिछले दो दशकों से इसकी मुख्य पहचान बन गया है। राष्ट्र को निगम के बतौर इस नव–उदारवादी तर्क का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अक्सर भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के बतौर अक्सर सम्बोधित करते हैं। उनके मामले में यह लोकप्रियता प्राप्त उपाधि विशेष तौर पर प्रचलित हो गयी है क्योंकि उन्हें 1990 के दशक के पूर्वार्ध से अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक के नेतृत्व में किये गये आर्थिक सुधारों का मुख्य कर्णधार माना जाता है।
>
> दूसरा निगमों के साथ साथ विश्व बैंक जैसी वैश्विक निकाय भारत में सामाजिक स्तर पर आधिकाधिक सुधार शुरू करने में लगती गयी हैं। यह व्यापक रूप से प्रचलित धारणा कि भारत सामजिक सांस्कृतिक रुकावटों के कारण ही वैश्विक आर्थिक शक्ति स्रोत के बतौर अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने में असफल है। भ्रष्टाचार की संस्कृति – सरकार के भीतर पारदर्शिता की कमी, घूसखोरी और भाई–भतीजावाद–को बाजार सुधारों को पूरा करने में मुख्य रुकावटों में से एक माना जाता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार

विरोधी अभियान को कई निगम नियोजित अखबारों और टीवी चैनलों और निगमित क्षेत्र से भारी समर्थन मिला है। तीसरा न सिर्फ भ्रष्ट सरकार को भारत के महाशक्ति के बतौर उठने के खिलाफ पाया गया है बल्कि खुद सरकार को ही इस लक्ष्य की ओर जाने में बाधा के तौर पर देखा जाता है। भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिरोध आंदोलन का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि सरकार को भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोत और गंगोत्री के तौर पर देखा जाता है। सोचने की यह लोकप्रिय दृष्टि की दिशा नव–उदारवादी विश्वास के इस दृष्टिकोण से मेल खाती है कि 'कम सरकार और ज्यादा बाजार' आर्थिक वृद्धि और समृद्धि का रास्ता है। निगमों, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं और राजनीति विरोधी लोक लुभावन गुस्से के बीच गठबंधन राष्ट्र की नैतिक सफाई के नये एजेण्डा को समझने की कुंजी है। यह भारत में नैतिक पीड़ा के निगमों के तर्क की रूपरेखा को समझने का एक प्रयास है।'' (Ravinder Kaur, EPW, May,18-2012page-40-41)

अन्ना आंदोलन में संलग्न मध्यम वर्ग सिविल सोसाइटी–छात्र–एन.जी.ओ. गठजोड़ इसके प्रतिक्रियावादी एजेण्डे को आगे बढ़ाने में जुटा रहा। अन्ना आंदोलन पर समर्थन व्यक्त करते हुए अमेरिका ने कहा :

''भ्रष्टाचार या जिस भी मुद्दे को विरोध करने के लिए उपयुक्त समझते हों, के विरुद्ध शान्तिपूर्वक विरोध करने का भारतीय लोगों का अधिकार उनके अधिकारों के दायरे के भीतर आता है और हम उसका समर्थन करते हैं कि यह कार्यशील जनतंत्र का हिस्सा है।'' (India a strong and functioning democracy: the state department spokesman मार्क टोनरः jagran Post)

अन्ना आंदोलन नव–उदारवादी भारत की ओर तेजी से बढ़ने के लिए साम्राज्यवादियों–पूंजीपतियों की जरूरत को पूरा करने का आंदोलन था। इसके तीन नेता अरविंद केजरीवाल, किरन बेदी–अन्ना हजारे 'राकफेलर फाउण्डेशन' द्वारा संचालित रेमन मैगसेसे पुरुस्कार से सम्मानित थे मैगसेसे फिलीपिंस के कम्युनिस्टों का भारी दमन करने वाले राष्ट्रपति थे।

इस आंदोलन पर एन.जी.ओ. नेटवर्क का पूर्ण नियंत्रण था। टीम अन्ना की कोर कमेटी ही सभी निर्णय लेती थी। केजरीवाल का 'पब्लिक कॉज रिसर्च फाउण्डेशन', किरनबेदी का 'शांति' सरीखे एन.जी.ओ. के साथ ढेरों अन्य एन.जी.ओ. इसमें शामिल थे। केजरीवाल–मनीष सिसोदिया का एन.जी.ओ. जहां फोर्ड फाउण्डेशन से तो किरनबेदी का एन.जी.ओ. लेहमन ब्रदर्स व कोकाकोला से वित्तपोषित थे।

निष्कर्ष

गैर सरकारी संस्थायें जहां एक ओर कुछ राहत कामों को संचालित कर व्यवस्था के खिलाफ जनाक्रोश कम कर रही होती हैं वहीं दूसरी ओर जनाक्रोश को व्यवस्था के दायरे में समेट व्यवस्था की सेवा कर रही होती हैं।

बीते वर्ष में दुनिया भर में फूटे संघर्ष तीन दशकों से चली आ रही नव–उदारवादी नीतियों–व हालिया मंदी से बदहाल जनता के आक्रोश की अभिव्यक्ति थे। इन संघर्षों की आशंका साम्राज्यवादी–पूंजीपति वर्ग को तभी से थी जब से उसने इन नीतियों को अपना मजदूर मेहनतकशों पर हमला बोला था। इसीलिए उसने इसकी तैयारी हेतु 'नव वाम' 'उत्तर आधुनिकतावादी' विचारधारा गढ़ने के साथ जमीनी स्तर पर एन.जी.ओ. नेटवर्क स्थापित किया। ये एन.जी.ओ. विभिन्न पहचानों के साथ–साथ 'वैश्वीकरण विरोध' के एजेण्डे को भी उठाने के लिए गठित किये गये। वैचारिक स्तर पर सभी संघर्षों को स्वतंत्र विच्छिन्न कर वर्गीय राजनीति को धूमिल किया गया तो जमीनी स्तर पर एन.जी.ओ. नेटवर्क के जरिये इन संघर्षों को अपनी कैद में रखने का व्यवस्था ने इंतजाम किया।

लेकिन इतिहास शासकों की मर्जी से संचालित नहीं होता। इतिहास के अंत का उनका नारा 2011 में हवा हो चुका था। आर्थिक मंदी व नव–उदारवादी नीतियों के खिलाफ 2011 में फूटा संघर्ष जब और आगे बढ़ेगा तो इन संघर्षों में शामिल गैर सरकारी संगठनों को मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा तब शासक वर्ग को जनाक्रोश से बचाने वाला कोई नहीं होगा।

लेकिन यह सब अपने आप नहीं होगा। कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को इसके लिए तैयारी करनी होगी। गैर सरकारी संगठनों के मकड़जाल को जनता के बीच बेपर्द करना होगा।

आज खुद हिंदुस्तान में 33 लाख से अधिक एन.जी.ओ. कार्यरत है इनमें से ढेरों आधुनिक तरीके के होंगे।

एन.जी.ओ. नेटवर्क की इस वृहद स्थिति के प्रभाव में संशोधनवादी संगठन तो पहले ही आ चुके हैं आज जहां भारत के CPI-CPM के ढेरों संगठन एन.जी.ओ. के साथ मिलकर काम करते हैं वहीं कम्युनिस्ट क्रांतिकारी भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं हैं। खुले नहीं तो छिपे तरीके से दाता एजेंसियां कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को भ्रष्ट करने के प्रयासों में जुटी हैं।

ऐसे में वक्त की जरूरत है कि भारत व दुनिया के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी इन गैर सरकारी संगठनों की वास्तविक राजनीति को जनता के बीच उजागर करें। इनके वैचारिक हमले के बरक्स क्रांतिकारी राजनीति स्थापित करें और यहां तक कि तात्कालिक संघर्ष के मुद्दे पर इनसे मोर्चा बनाते हुए भी खासे सचेत रहें। हमारी सचेत कार्यवाहियां ही इनको जनता के बीच से खदेड़ने का माध्यम बनेंगी।